स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

सत्यमेव जयते

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार

www.mospi.gov.in

सत्यमेव जयते

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम
कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार

4 वर्ष की उपलब्धियाँ

MAKE IN INDIA

Digital India
Power To Empower

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

Smart City
MISSION TRANSFORM-NATION

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

PRADHAN MANTRI JAN-DHAN YOJANA
MERA KHATA BHAGYA VIDHATA

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत सुंदर भारत

सबका साथ सबका विकास

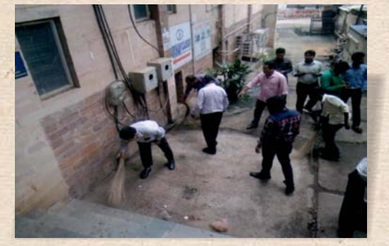

अवसंरचना परियोजनाओं की देखरेख

आधिकारिक सांख्यिकी के मूलभूत सिद्धांत (एफ पी ओ एस)

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में एफ पी ओ एस से संबधित संकल्प अंगीकार किया गया

भारत सरकार द्वारा जून, 2016 में एफ पी ओ एस अंगीकार किया गया

सिद्धांतों का उद्देश्य :

- आधिकारिक सांख्यिकीय व्यवस्था में वृत्तिक आत्मनिर्भरता, निष्पक्षता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देना और उसमें जनता का विश्वास बढ़ाना
- सरकार के कार्यनिष्पादन पर आम जनता द्वारा सुविचारित परिचर्चा तथा बेहतर मूल्यांकन को आसान बनाना
- आधिकारिक सांख्यिकी के उत्पादन तथा प्रसार में अच्छी कार्य-परम्पराओं तथा वृत्तिक आचार-नीति को बढ़ावा देना

इन सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए आधिकारिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय नीति का प्रारूप बनाया गया और लोगो के विचार आमंत्रित करने के लिए इसे सार्वजानिक मंच पर रखा गया

आधिकारिक सांख्यिकी के लिए गुणवत्ता आश्वासन संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश

सांख्यिकीय मामलों से सरोकार रखने वाले सरकारी अभिकरणों द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल, 2018 में अधिसूचित

सांख्यिकीय उत्पादों को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा समर्थित व्यापक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क के अनुसार वैश्विक मानकों के समरूप करना

सरकारी एजेंसियों की सांख्यिकीय उत्पादों में सुधार लाने में सहायता करना

अवसंरचना परियोजनाओं की देखरेख

MoSPI OCMS

समय एवं लागतवृद्धि के संबंध में ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के माध्यम से 150 करोड़ रू. तथा इससे अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की चालू परियोजनाओं की निगरानी की जाती है

ओसीएमएस परियोजना एजेंसियों को परियोजनाओं की स्थिति वास्तविक समय में निरंतर अपलोड करने में सक्षम बनाती है

गहन निगरानी के परिणामस्वरूप विगत चार वर्षों में कुल 311 परियोजनाएं (4.5 लाख रू. करोड़ की लागत वाली) पूरी की गई है ।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)

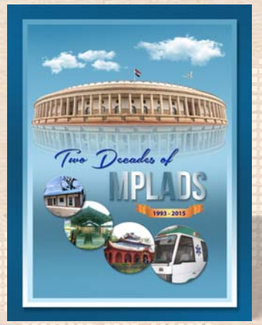

दिनांक 27.03.2018 को राज्य सभा के सभी माननीय संसद सदस्यों के लिए एक ओपन हाउस का आयोजन किया गया

एमपीलैड्स दिशा निर्देशों पर एक पाकेट पुस्तिका प्रकाशित की गई

एक ई-पुस्तिका भी प्रकाशित की गई

नागरिकों के सुझाव सहित सभी हितधारकों के उपयोग के लिए एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल विकसित किया गया

विगत चार वर्षों के दौरान संस्तुत 3.5 लाख कार्यों में 2.7 लाख से अधिक के कार्य पूरे किए गए

सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश

अप्रैल, 2018 में अधिसूचित

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांकों के उत्पादन तथा उनके प्रसार के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

सरकारी सांख्यिकीय अभिकरणों के उपयोग हेतु

विभिन्न अभिकरणों के संकार्यों में सामंजस्य बिठाने को प्रोत्साहित करता है

सूचकांकों की गुणवत्ता में सुधार को प्रोत्साहित करता है

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 में संशोधन

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर उत्तरदाताओं से आंकड़े एकत्रित करने हेतु वैधानिक ढांचा प्रदान करता है

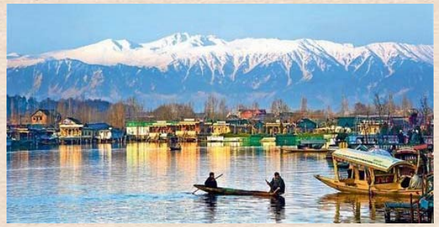

सांख्यिकी संग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 2017 सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 का अधिकार क्षेत्र का विस्तार जम्मू तथा कश्मीर राज्य में करता है

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)

संसद सदस्यों को नागरिक केन्द्रित विकासात्मक गतिविधियों में योगदान करने के लिए सक्षम बनाना

आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में कई संशोधन किए गए

- गहन प्राकृतिक आपदा के मामले में माननीय संसद सदस्यों द्वारा निधियों में योगदान की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई
- कौशल विकास के लिए उपकरणों की खरीद की अनुमति दी गई
- तिपहिया साइकिल, कृत्रिम अंगों तथा दृष्टि एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी गई
- केन्द्र/संघ राज्य क्षेत्रों या स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्थलों पर स्थाई वाई-फाई प्रणालियां स्थापित करने की अनुमति दी गई
- 'अटल ज्योति योजना' के तहत सौर प्रकाश प्रणालियों का प्रावधान किया गया

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

आर. सी. बोस सेंटर फार क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्यूरिटी की स्थापना की गई

एम. टेक. पाठ्यक्रम 2018-19 से आरंभ किया गया

सैद्धांतिक, व्यावहारिक सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र में शोध कार्य करने के लिए कोलकाता में एक प्रतिचयन तथा आधिकारिक सांख्यिकीय यूनिट (एसओएसयू) खोला गया

2015 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान कोलकाता के सहयोग से व्यवसाय विश्लेषण में 2 वर्षीय परास्नातक डिप्लोमा कार्यक्रम का आरम्भ किया गया

करीब 2700 तकनीकी पत्र प्रकाशित किए गए

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

वर्ष 2015 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा में, 'ट्रांसफर्मिंग अवर वर्ल्ड : 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' जिसमें वर्ष 2030 तक हासिल किए जाने वाले 17 सतत विकास लक्ष्य तथा सम्बद्ध 169 ध्येय शामिल हैं, संबंधी संकल्प अंगीकार किया

इन लक्ष्यों तथा ध्येयों के संबंध में देश की प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए मंत्रालय ने एक राष्ट्रीय संकेतक ढांचा विकसित किया है

आंकड़ा संग्रहण तथा प्रसार के लिए नई प्रौद्योगिकी का उपयोग

कारगर आंकड़ा प्रसार हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन) साधन किट सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इकाई-स्तरीय आंकड़ों का वेब-आधारित सर्वेक्षण आंकड़ा सूची/माइक्रो डेटा आर्काइव

सर्वेक्षण के समापन तथा परिणामों को जारी करने के बीच समय अंतराल को घटाते हुए तीव्र आंकड़ा विधायन हेतु पीएलएफएस में उपयोग के लिए कम्प्यूटर सहायता प्राप्त वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई) तकनीक का आरम्भ ।

प्रतिदर्श सर्वेक्षणों में फ्रेम के रूप में उपयोग हेतु शहरी मानचित्रों का अंकीकरण

वेबपोर्टल द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के लिए आंकड़ा संग्रहण

कार्यविधियां, ई-गवर्नेंस तथा आंकड़ा प्रसार का मानकीकरण

आईएसओ 9001:2008 प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया

- राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (सी एस ओ)
- अभिकल्प एवं अन्वेषण प्रभाग (एन एस एस ओ)

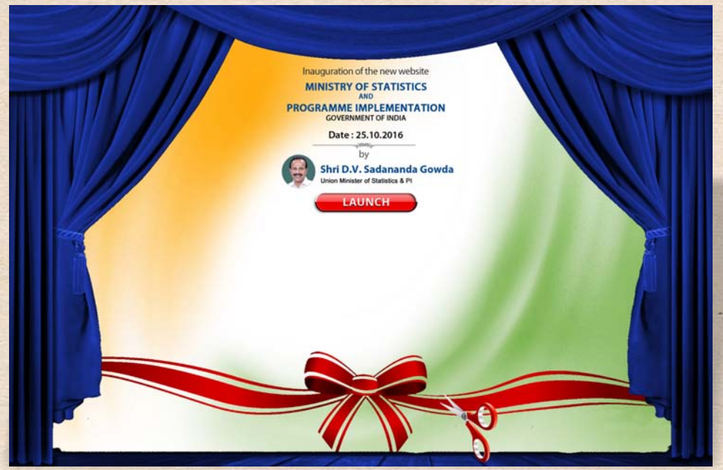

भारत सरकार के वेब साइट्स के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार अक्टूबर, 2016 में मत्रांलय की नई वेब साइट आरम्भ की गयी

जारी किए गए प्रकाशन

मई 2014 से जारी किए गए प्रकाशन

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण

समुच्चय राष्ट्रीय लेखा

निम्नलिखित पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के रिपोर्ट

- भारत में शिक्षा
- भारत में स्वास्थ्य
- भारत में पारिवारिक ऋणग्रस्ता
- भारत में घरेलू पर्यटन
- भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यमों की परिचालनात्मक विशेषताएं
- भारत में पारिवारिक पूंजीगत व्यय
- भारत में पशुधन स्वामित्व
- भारत में पारिवारिक परिसंपत्तियां तथा देयताएं

हाल ही में जारी की गई कुछ रिपोर्ट

भारत में बच्चे - एक सांख्यिकीय निरूपण, 2018

भारत में स्त्री तथा पुरूष 2017

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य- भारत का अन्तिम कंट्री रिपोर्ट 2017

सार्क विकास लक्ष्य -भारत कंट्री रिपोर्ट 2017

भारत में युवा 2017

एनवी-स्टैट्स इंडिया 2018

आधिकारिक सांख्यिकी में नवाचार को बढ़ावा देना

आधिकारिक सांख्यिकी में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2018 का आयोजन किया गया

इंजीनियरिंग छात्रों की टीमों द्वारा विकसित डिजिटल समाधानों को अंगीकरण के लिए छांटा गया

सांख्यिकी आंकड़ों के भण्डारण एवं उन्नत विश्लेषण के लिए राष्ट्रीय आधिकारिक सांख्यिकी आंकड़ा भंडार की स्थापना करने के लिए कदम उठाए गए

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2018 का ग्रैंड फिनाले

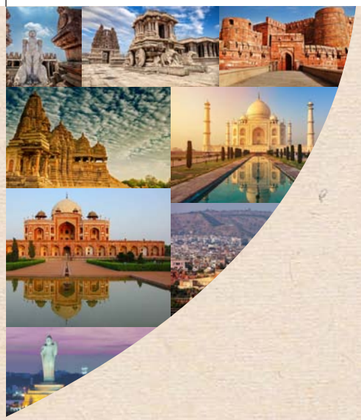

एन एस एस ओ के सर्वेक्षण

एन एस एस ओ ने निम्नलिखित विषयों पर अखिल भारत सर्वेक्षण किए

सेवाओं तथा टिकाऊ वस्तुओं पर पारिवारिक उपभोग व्यय (2014-15)

घरेलू पर्यटन व्यय (2014-15)

स्वच्छता स्तर पर त्वरित सर्वेक्षण (मई-जून, 2015)

विनिर्माण, व्यापार तथा अन्य सेवा सेक्टर (निर्माण को छोड़कर) में अनिगमित गैर-कृषि उद्यम (2015-16)

सेवा सेक्टर का सर्वेक्षण (2016-17)

परिवार उपभोक्ता व्यय (2017-18)

सामाजिक उपभोग : स्वास्थ्य (2017-18)

सामाजिक उपभोग : शिक्षा (2017-18)

आर्थिक गणना

छठी आर्थिक गणना के अखिल भारत परिणाम
वर्ष 2016 में जारी किए गए

आर्थिक गणना विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में सलंग्न समस्त उद्यमों
तथा प्रतिष्ठानों की सूची उपलब्ध कराती है

क्रियाकलापों की प्रकृति, रोजगार तथा अवस्थिति के विवरण उपलब्ध कराती है

आधिकारिक सांख्यिकी में क्षमता निर्माण

आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) सरकारी सांख्यिकी
का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक शीर्ष प्रशिक्षण अकादमी है

भारत वैश्विक सांख्यिकीय प्रशिक्षण नेटवर्क संस्थान (जीआईएसटी)
का संस्थापक सदस्य बना

पिछले 4 वर्षों के दौरान 132 पाठ्यक्रमों में 2700 से अधिक कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया

एन एस एस ओ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न सर्वेक्षणों में आंकड़ा संग्रहण तथा संकलन के लिए
प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है

सीएसओ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके सांख्यिकीय उत्पाद जैसे राज्य घरेलू उत्पाद,
जिला घरेलू उत्पाद, आईआईपी, सीपीआई, आदि विकसित करने तथा उनमें सुधार
करने के लिए तकनीकी सहायता/मार्गदर्शन प्रदान करता है

राज्य सांख्यिकीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

केंद्र तथा राज्य स्तर पर सांख्यिकीय गतिविधियों से सम्बंधित सामान्य मुद्दों पर विचार विमर्श को सुगम बनाने हेतु केंद्र तथा राज्य सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलन (सीओसीएसएसओ) प्रतिवर्ष आयोजित किये गये

14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सांख्यिकी प्रणाली सुधारने के लिए 276 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई गई

इसके द्वारा स्थानिक नियोजन हेतु ग्राम/खंड विकास स्तर पर सांख्यिकी संकलन में राज्यों को मदद मिली है

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

रोजगार के आंकड़े कमतर अंतरालों पर प्राप्त करने के लिए अप्रैल, 2017 में आरंभ किया गया

नगरीय क्षेत्रों में तिमाही बदलावों को मापने के लिए

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों के वार्षिक अनुमान तैयार करने के लिए

टैबलेट्स में आंकड़े प्रविष्ट करने के लिए कम्प्यूटर सहायित निजी साक्षात्कार (सी ऐ पी आई) विधि का प्रयोग किया जा रहा है

जीडीपी, आईआईपी तथा सीपीआई के आधार वर्ष में संशोधन

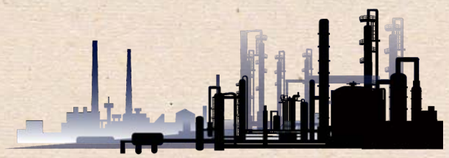

अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों को पकड़ने के लिए वृहद-आर्थिक संकेतकों के आधार वर्ष का संशोधन

सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) तथा औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आईआईपी) का आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित करके 2011-12 किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार वर्ष 2010 से बदलकर 2012 किया गया

अर्थव्यवस्था की प्रगति के बेहतर मूल्यांकन में मदद करता है

साक्ष्य आधारित नीति निर्धारण को प्रोत्साहित करता है

जी डी पी तथा आई आई पी के आधार वर्ष को 2017-18 एवं सी पी आई आधार वर्ष को 2018 में आगे बदलने के लिए कदम उठाये गए

उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में पहल

एनएसएसओ के विभिन्न सर्वेक्षणों को सम्पादित करने तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सर्वेक्षण को सुदृढ़ बनाने तथा इसके पहुंच का विस्तार करने के लिए उत्तर- पूर्वी राज्यों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को 14.80 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

सिक्किम, मिजोरम तथा मणिपुर को उनकी सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने हेतु 46.76 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए

उत्तर-पूर्व में आइजोल (मिजोरम) तथा ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) स्थित एनएसएसओ के दो नए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने तथा अगरतला (त्रिपुरा) एवं इंफाल (मणिपुर) स्थित दो उप क्षेत्रीय कार्यालय को समुन्नत करने की प्रक्रिया आरंभ की गई

आईएसआई के तेजपुर (असम) केंद्र को अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई

उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए राष्ट्रीय लेखा, आईआईपी, एसएसएसपी आदि में अनेक कार्यशालाएं आयोजित की गई

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में पहल

भारत ने नवम्बर, 2016 में जयपुर में आयोजित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 8वीं बैठक की मेजबानी की

भारत ने आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में क्षेत्रीय सह-भागिता तथा पहलों को बढ़ाने के लिए अगस्त, 2016 में सार्क सांख्यिकीय संगठनों (सार्क स्टैट) के प्रमुखों की 8वीं बैठक की मेजबानी की

मंत्रलय ने 23-27 अक्टूबर, 2017 को नई दिल्ली में सेवा सांख्यिकी पर वूरबर्ग समूह की 32वीं बैठक की मेजबानी की थी

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के संबंध में पहल

भारत में मार्च, 2016 में न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के 47वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी) 2011 के मूल्यांकन के लिए गठित फ्रेंड आफ चेयर ग्रुप की बैठक की सह-अध्यक्षता की

भारत ने वांशिगटन डीसी, यू.एस.ए. में नवंबर, 2016 में आयोजित आईसीपी गवर्निंग बोर्ड की बैठक तथा हनोई वियतनाम में जनवरी 2017 में आयोजित क्षेत्रीय परामर्शदात्री बोर्ड की बैठक की सह-अध्यक्षता की

भारत ने अक्टूबर, 2017 में जेनेवा में आयोजित यू एन सिटी ग्रुप आन इनफॉर्मल सेक्टर स्टैटिस्टिक्स (दिल्ली ग्रुप) की अध्यक्षता की

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार